विवरण-- II

उन कर्मकारों की देशवार संख्या जिन्हें वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान उत्प्रवास अनुमतियां उ० एं० अ० नहीं पृष्ठांनों को अनुमति प्रदान की गई:—

देश	1992	1993	1994
बहरीन	16,458	15,622	13,806
ओमान	40,900	29,056	25,142
संयुक्त अरब अमीरात . .	60,493	77,066	75,762
किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया . .	2,65,180	2,69,639	2,65,875
कुवैत	19,782	26,981	24,324
अन्य . .	13,971	19,974	20,476
कुल	4,16,784	4,38,338	4,25,385

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

6821. श्री रामजेठमलानी:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् 1994 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगभग 76,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है ;

(ख) यदि नहीं तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इनमें से पुन: काम करने के इच्छुक कर्मचारियों को प्रशिक्षण इत्यादि देकर पुन: नियोजित करने की योजना आरम्भ की है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को पुन: रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-3-95 की स्थिति के अनुसार 61 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 75,756 कर्मकारों ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता प्राप्त स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त किया।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय नवीकरण निधि अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक पुर्नसंरचना के परिणाम स्वरूप योक्तीकृत कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण और पुर्ननियोजन का खर्च पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अन्तर्गत कर्मकारों को सलाह देने, पुन:प्रशिक्षित करने और पुर्ननियोजित करने संबंधी योजना को 9-9-93 को अनुमोदित किया गया था। अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, इंदौर और कानपुर स्थित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्थापित कर्मचारी सहायता केन्द्रों के माध्यम

से पांच पायलट योजनाएं चलाई गई हैं। वस्तुत: इन केन्द्रों से आशा की जाती है कि ये यौक्तीकृत कर्मकारों को रोजगार बाजार में पुन: प्रवेश करने अथवा स्वत: रोजगार शुरू करने के लिए पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। वे ऋण, कच्चे माल, विपणन और व्यापार सलाह प्रदान करने में भी सहायक होंगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-3-95 की स्थिति के अनुसार, इन कर्मचारी सहायता केन्द्रों ने 5287 कर्मकारों को सलाह प्रदान की, 1273 कर्मकारों को पुनर्प्रशिक्षित किया और 145 कर्मकारों को पुनर्नियोजित किया। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की कर्मकार पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन योजना के लिए पूरे देश में स्थित 48 और स्थानों की पहचान की गई है। श्रम मंत्रालय भी 15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में यौक्तीकृत कर्मकारों के लिए पुनर्प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

Labour force in organised sector in the country

6822. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of LABOUR be please to state:

(a) what is the total labour force in the organised sector in the country;

(b) what is the labour force in Public Sector Undertakings both State and Central Government Undertakings in the country;

(c) what is the estimated labour force in the sick Industrial Undertaking in the country; and

(d) how Government are going to rehabilitate the labour force likely to be retrenched from the sick units?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) 27.18 million (as on 31.3.93).

(b) As on 31-3-90 about 23 lakh persons were employed in 244 Central Public Sector Undertakings. Information on employment in State Public Sector Undertakings is being collected;

(c) As on December 31, 1994, there were 989208 workers in 1292 sick companies registered with the Board for Industrial and Financial Reconstruction.

(d) Industrial Disputes Act, 1947 provides for payment of compensation to the workers in the event of retrenchment or closure. Government has also established the National Renewal Fund as a social safety net for the workers affected by industrial restructuring. The Fund, inter alia, provides for assistance to cover the costs of retraining and redeployment of affected workers.

Implementation of Bachawat Award for journalists

3823. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) how many newspapers have implemented the Bachwat Award for the working Journalist, State-wise;

(b) how many newspapers are required to implement the award on the basis of their circulation figures available with Registrar of newspapers in India;

(c) whether the Ministry of Labour and the Ministry of Information and Broadcasting are coordinating in this regard to prepare the list of newspapers who have to implement the award;

(d) whether Government are aware that a large number of newspapers are having circulation exceeding 15000 and getting advertisements and news print quota on the basis of circulation and not implementing the Wage Board Accord; and

(e) what action Government propose to initiate to implement the Wage Board Award to working Journalist?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (e) Onus for the implementation of